

57th GST COUNCIL MEETING

Major Recommendation

8 October 2026
(PIB Press Release)



1

GST ARREST

Section 69 के तहत Arrest Powers हटाने का प्रस्ताव

वर्तमान प्रावधान

- CGST Act, 2017 की Section 69 के तहत कुछ मामलों में Proper Officer को Arrest करने की Power है।
- यह Power गंभीर मामलों में, निर्धारित शर्तों और प्रक्रिया के अधीन उपयोग की जाती है।



GST Council की Recommendation

SECTION
69

TO BE
OMITTED

- CGST Act की Section 69 को हटाने (omit) का प्रस्ताव किया गया है।
- GST के अंतर्गत Arrest Powers पूरी तरह से वापस लेने की सिफारिश की गई है।
- टैक्स प्रशासन को अधिक व्यवसाय-अमुकुल (taxpayer friendly) और गैर-उत्पीड़नकारी बनाने का उद्देश्य है।



मुख्य बातें

- ✓ Section 69 को हटाने का प्रस्ताव।
- ✓ GST के अंतर्गत Arrest Powers समाप्त।
- ✓ यह Prosecution से अलग विषय है। (Section 132 लागू रहेगा, उच्च Monetary Limit के साथ)



संभावित लाभ

- ✓ व्यापारिक समुदाय में विश्वास और सुरक्षा बढ़ेगी।
- ✓ छोटे और genuine करदाताओं पर अनावश्यक कार्रवाई का जोखिम कम होगा।
- ✓ Tax administration अधिक पारदर्शी और व्यवसाय-अमुकुल बनेगा।



ध्यान देने योग्य बात

- यह केवल Recommendation है, अभी लागू कानून नहीं।
- संबंधित कानून संशोधन, अधिसूचना और परिपत्र जारी होने के बाद ही प्रभावी होगा।
- Criminal Prosecution (Section 132) जारी रहेगा, जिसके लिए ₹5 करोड़ की नई सीमा प्रस्तावित है।

57th GST COUNCIL MEETING

Major Recommendation



October 2026
(PIB Press Release)



2

PROSECUTION

Monetary Threshold ₹1 करोड़ से ₹5 करोड़



वर्तमान प्रावधान

- GST के अंतर्गत कुछ गंभीर अपराधों के मामलों में Monetary Threshold ₹1 करोड़ है।
- इससे अधिक राशि होने पर Prosecution किया जा सकता है (Section 132).

₹1 करोड़
(Existing Threshold)



GST Council की Recommendation

- Prosecution के लिए Monetary Threshold ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ करने का प्रस्ताव किया गया है।
- इससे छोटे और genuine businesses को अनावश्यक Prosecution से राहत मिलेगी।

SECTION 132



Key Points



Threshold ₹1 करोड़ से ₹5 करोड़.



Small and genuine businesses को राहत.



Serious offences पर ही Prosecution लागू रहेगा।

Practical Impact



अनावश्यक Criminal Prosecution का जोखिम कम होगा।



Business community के लिए Ease of Doing Business.



Tax administration का फोकस बड़े और गंभीर मामलों पर रहेगा।

Important Note



यह केवल Recommendation है, अभी लागू कानून नहीं है।



संबंधित कानून संशोधन, अधिसूचना और परिपत्र जारी होने के बाद ही प्रभावी होगा।



अन्य Offences और Conditions यथावत रह सकते हैं।

57th GST COUNCIL MEETING

Major Recommendation

8 October 2026
(PIB Press Release)



3

GENERAL PENALTY

अधिकतम ₹25,000 से ₹10,000



वर्तमान प्रावधान

Section 125 के तहत
General Penalty की
अधिकतम सीमा

₹25,000
(Maximum)



GST Council की Recommendation

Section 125 के तहत
General Penalty की
अधिकतम सीमा

₹10,000
(Maximum)



Key Points

- ✓ Section 125 की Maximum General Penalty ₹25,000 से ₹10,000 करने का प्रस्ताव।
- ✓ इससे छोटे और genuine businesses को राहत मिलेगी।
- ✓ Compliance के लिए बेहतर माहौल बनाने का उद्देश्य।



Practical Impact

- ✓ Minor offences पर लगने वाली Penalty का वित्तीय बोझ कम होगा।
- ✓ छोटे व्यापारियों और स्टार्टअप्स को राहत।
- ✓ Tax compliance में सुधार और सहायक माहौल।



Important Note

- ! यह Section 125 की General Penalty है, सभी प्रकार की GST Penalties पर लागू नहीं।
- ! यह अभी केवल Recommendation है, अभी लागू कानून नहीं है।
- ! अंतिम प्रभाव संबंधित कानून संशोधन, Notifications और Circulars के बाद ही होगा।

57th GST COUNCIL MEETING

Major Recommendation

8 October 2026
(PIB Press Release)



4

GST NOTICE

₹10,000 से कम Tax Amount पर SCN नहीं



वर्तमान प्रावधान

- नियत मामलों में कम Tax Amount पर भी Show Cause Notice (SCN) जारी हो सकता है (Sections 73, 74, 74A).



GST Council की Recommendation

- ₹10,000 से कम Tax Amount (CGST + SGST + IGST + Cess मिलाकर) पर Show Cause Notice (SCN) जारी नहीं किया जाएगा.
- यह प्रावधान Sections 73, 74 और 74A के अंतर्गत प्रस्तावित है.



Key Points

- ✓ Threshold: ₹10,000 (CGST + SGST + IGST + Cess).
- ✓ Applicable to Sections 73, 74 and 74A.
- ✓ Small taxpayers को unnecessary litigation से राहत.



Practical Impact

- ✓ छोटे Tax Disputes में Notices की संख्या कम होगी.
- ✓ Compliance burden कम होगा.
- ✓ Genuine taxpayers को राहत मिलेगी.
- ✓ Department और taxpayers के बीच अनावश्यक विवाद कम होंगे



Important Note

- ! यह Tax Liability को माफ नहीं करता है; केवल SCN जारी न करने का proposed threshold है.
- ! यह अभी Recommendation है, अभी लागू कानून नहीं है।
- ! अंतिम प्रभाव संबंधित कानून संशोधन, Notifications और Circulars के बाद ही होगा।

57th GST COUNCIL MEETING

Major Recommendation

8 October 2026
(PIB Press Release)



5

GST REGISTRATION

Registration, Amendment और Cancellation को सरल बनाना

GST



1 REGISTRATION

- ✓ Registration process को और सरल बनाया जाएगा।
- ✓ REG-01 में documents के लिए drop-down options और clear guidelines दी जाएंगी।
- ✓ अनावश्यक queries और rejections कम होंगे।



2 AMENDMENT

- ✓ Majority of amendments automatic होंगे (PoB को छोड़कर)
- ✓ Business details update करने में Officer approval का हंतजार नहीं करना पड़ेगा।
- ✓ Rule 14A में PPoB भी शामिल किया गया है।



3 CANCELLATION

- ✓ Pending Returns और outstanding dues clear होने पर cancellation process आसान होगा।
- ✓ Certain cases में phased automatic cancellation का mechanism प्रस्तावित है।
- ✓ Inactive या non-operational GSTIN को बंद करना आसान होगा।



Key Highlights

- ✓ Simplified and transparent registration process
- ✓ Drop-down options for documents in REG-01
- ✓ Most amendments to be processed automatically
- ✓ Inclusion of PPoB in Rule 14A
- ✓ Simpler and faster cancellation mechanism



Benefits for Taxpayers

- ✓ Faster and easier registration
- ✓ Less queries and rejections
- ✓ Quick updates to business details
- ✓ Reduced compliance burden
- ✓ Easy closure of non-operational GSTIN



Who Will Benefit?

- ✓ New businesses and startups
- ✓ Existing taxpayers needing amendments
- ✓ Businesses with multiple locations
- ✓ Inactive or seasonal businesses



57th GST COUNCIL MEETING

Major Recommendation

8 October 2026
(PIB Press Release)



6

GST RETURNS

GSTR-1, GSTR-3B, GSTR-2B और IMS में बेहतर Reconciliation



GSTR-1



Outward Supplies
(Sales/Invoices)



GSTR-3B



Tax Payment
(Summary Return)



BETTER RECONCILIATION



GSTR-2B



Inward Supplies
(ITC Details)



IMS



Inward Supplies
(Monthly Statement)



What is the Recommendation?

- ✓ GSTR-1, GSTR-3B, GSTR-2B और IMS में बेहतर Reconciliation की सुविधाएँ दी जाएंगी।
- ✓ Output Tax और ITC Mismatches को कम करने के लिए Reporting और Correction Mechanism सरल किया जाएगा।
- ✓ यह सुधार April 2027 Return Period से प्रस्तावित है।



Key Features / Improvements

- ✓ Forms के बीच data matching और reconciliation और आसान होगा।
- ✓ Mismatches को identify करने और correct करने के लिए बेहतर tools मिलेंगे।
- ✓ IMS data का बेहतर उपयोग और integration होगा।
- ✓ Taxpayer को compliance में सुविधा मिलेगी और notices में कमी आएगी।
- ✓ More accurate reporting से genuine taxpayers को राहत मिलेगी।



Benefits for Taxpayers

- ✓ GSTR-1 vs GSTR-3B mismatch कम होगा।
- ✓ 2B vs Books reconciliation आसान होगा।
- ✓ ITC claims अधिक सही और सुरक्षित होंगे।
- ✓ Compliance burden कम होगा।
- ✓ Notices और अनावश्यक विवादों में कमी आएगी।
- ✓ Return filing अधिक accurate और seamless होगा।

57th GST COUNCIL MEETING

Major Recommendation

8 October 2026
(PIB Press Release)



7

GST REFUND

90% Provisional Refund का Automated Mechanism



How it Works ?

1 Refund Application Filing



2 System-based Risk Assessment



3 90% Provisional Refund (Automated)



4 Remaining 10% After Verification



5 Faster Refund to Improve Working Capital



Key Highlights

- ✓ 90% Provisional Refund का Automated Mechanism लागू किया जाएगा।
- ✓ Genuine taxpayers को जल्दी Refund मिलेगा।
- ✓ Refund process को faster और system-based बनाया जाएगा।
- ✓ Manual intervention कम होगा।
- ✓ Exporters और low-risk taxpayers को बड़ी राहत मिलेगी।



Benefits for Taxpayers

- ✓ Faster and quicker refund processing
- ✓ Improved working capital
- ✓ Less compliance burden
- ✓ Transparency and predictability
- ✓ Support to exporters and genuine taxpayers
- ✓ Better cash flow for businesses



Objective

- ✓ To provide liquidity to businesses
- ✓ To reduce blockage of working capital
- ✓ To improve ease of doing business
- ✓ To build a more trusted and transparent refund system



57th GST COUNCIL MEETING

Major Recommendation

8 October 2026
(PIB Press Release)



8

INPUT TAX CREDIT

Section 17(5) में कुछ Blocked ITC Restrictions हटाना



पहले (Existing Provision)

Section 17(5) के तहत कुछ इनपुट पर ITC ब्लॉक था, जैसे :

- ✗ Motor Vehicles (कुछ मामलों में)
- ✗ Food & Beverages
- ✗ Club, Health & Fitness
- ✗ Beauty & Cosmetic
- ✗ Life & Health Insurance
- ✗ Rent-a-Cab / Travel Benefits
- ✗ Personal Use Items
- ✗ और अन्य निर्दिष्ट वस्तुएँ/सेवाएँ



अब
(Recommended Change)

अब (GST Council Recommendation)

Section 17(5) में कुछ Blocked ITC Restrictions हटाने का प्रस्ताव, ताकि वैध बिजनेस इनपुट पर ITC लिया जा सके।

- ✓ कुछ वस्तुओं/सेवाओं पर लगा ITC प्रतिबंध हटेगा।
- ✓ वैध व्यावसायिक उपयोग के लिए ITC उपलब्ध होगा।
- ✓ जेनुइन व्यवसायों को इनपुट कॉस्ट पर राहत मिलेगी।
- ✓ ITC के दायरे को व्यावहारिक और वर्तमान व्यावसायिक जरूरतों के अनुरूप बनाया जाएगा।



Key Highlights

- ✓ Section 17(5) में कुछ Blocked ITC Restrictions हटाने का प्रस्ताव।
- ✓ वैध व्यावसायिक उपयोग के लिए ITC की विस्तृत उपलब्धता।
- ✓ Compliance को आसान और व्यावहारिक बनाना।
- ✓ Genuine businesses को इनपुट कॉस्ट पर राहत।



Expected Benefits

- ✓ इनपुट कॉस्ट कम होगी।
- ✓ व्यवसाय की कार्यशील पूंजी (Working Capital) में सुधार।
- ✓ Compliance विवादों और दिस्प्यूट्स में कमी।
- ✓ ईमानदार करदाताओं के लिए अनुकूल माहौल।



Who Will Benefit?

- Manufacturers
- Traders & Distributors
- Service Providers
- Businesses with business-related vehicles, travel, insurance, F&B आदि।
- Genuine taxpayers

57th GST COUNCIL MEETING

Major Recommendation

8 October 2026
(PIB Press Release)



9

E-WAY BILL

Intelligence-Based Interception और Transit-State Restrictions

E-WAY BILL



Current Situation

- ✗ E-Way Bill checking kai baar routine basis par hoti hai।
- ✗ Transit states mein bhi baar-baar rok kar verification kiya jata hai।
- ✗ Har vehicle ki physical checking se genuine businesses ko pareshani hoti hai।
- ✗ Is wajah se goods ki movement mein delay hota hai और logistics cost badh jati hai।



अब
(Recommended Change)

Proposed Change

- ✓ Intelligence-based risk analysis के आधार पर ही interception होगी।
- ✓ Random और routine checking को कम किया जाएगा।
- ✓ Genuine businesses के goods की smoother movement सुनिश्चित की जाएगी।
- ✓ Transit-state में unnecessary restrictions कम किए जाएंगे।
- ✓ Technology और data analytics का उपयोग कर targeted checking की जाएगी।



Key Highlights

- ✓ Intelligence-based risk profiling for interception.
- ✓ Transit-state restrictions to be rationalised.
- ✓ Focus on genuine businesses and smooth movement of goods.
- ✓ Use of technology, data analytics and authorised interception.



Expected Benefits

- ✓  Faster and smoother movement of goods.
- ✓  Reduced logistics cost.
- ✓  Less harassment for genuine businesses.
- ✓  Better compliance and targeted action against high-risk cases.



Who Will Benefit?

-  Manufacturers
-  Traders & Distributors
-  Logistics & Transporters
-  MSMEs and Genuine Businesses

57th GST COUNCIL MEETING

Major Recommendation

8 October 2026
(PIB Press Release)



10

EXPORT OF SERVICES

Foreign Branch और Place of Supply से संबंधित राहत



What is the Recommendation?

- ✓ Export of services से संबंधित Foreign Branch के मामलों में राहत देने का प्रस्ताव।
- ✓ Place of Supply (PoS) से संबंधित certain provisions को सरल और व्यवहारिक बनाने की सिफारिश।
- ✓ Export of services की qualify करने की प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट और आसान बनाना।
- ✓ Compliance burden कम करने और genuine exporters को सुविधा देना।



Key Areas of Relief

- 1 Foreign Branch Transactions**
Indian company द्वारा अपने foreign branch को दी जाने वाली services पर राहत।
- 2 Place of Supply (PoS)**
Place of Supply की व्याख्या में clarity और practical relief।
- 3 Export Qualification**
Export of services qualify करने के मानदंडों को सरल बनाना।
- 4 Reduced Compliance**
Documentation और procedural requirements को आसान बनाना।



Benefits for Businesses

- ✓ Indian companies को foreign branches को services देने में clarity मिलेगी।
- ✓ Export of services पर compliance आसान होगा।
- ✓ Place of Supply से संबंधित विवादों में कमी आएगी।
- ✓ Genuine exporters को provisions का सही लाभ मिलेगा।
- ✓ Global operations करने वाली Indian companies के लिए बड़ा राहत।



Who Will Benefit?

- Indian Companies with Foreign Branches
- Exporters of Services
- IT / ITES & BPO Companies
- Consultants & Professionals
- Global Service Providers

57th GST COUNCIL MEETING

Major Recommendation

8

October 2026
(PIB Press Release)



11

SMALL TAXPAYERS

₹5 करोड़ तक B2C Businesses के लिए Proposed ARQP Scheme

ARQP
SCHEME



What is ARQP Scheme ?

Annual Return and Quarterly Payment (ARQP) Scheme

यह एक प्रस्तावित वैकल्पिक योजना है, जो ₹5 करोड़ तक टर्नओवर वाले B2C (Consumer-Facing) Businesses के लिए होगी।

इस स्कीम का उद्देश्य छोटे कारोबारियों के लिए GST Compliance को और सरल बनाना है।



How it will work ?

1



Quarterly GST Payment
हर quarter में simple payment

2



Annual Return Filing
सिर्फ 1 बार साल में return

3



Simpler Compliance
कम compliance burden

4



For B2C (Consumer-Facing) Businesses
Retailers, Traders, Service Providers
जिनका direct customers से कारोबार है



Key Highlights



- ₹5 करोड़ तक टर्नओवर वाले B2C Businesses के लिए प्रस्तावित योजना।
- Quarterly payment और Annual return का मॉडल।
- Compliance process को सरल और आसान बनाना।
- छोटे कारोबारियों के लिए राहत और ease of doing business।
- यह एक optional scheme होगी (in-principle approval)।



Examples of Eligible Businesses



Retail Shops



Traders & Wholesalers (B2C)



Restaurants & Cafés



Service Providers (B2C)



D2C Brands & Small E-commerce Sellers



Expected Benefits



- Compliance burden कम होगा।
- Time और cost की बचत।
- Small businesses के लिए business easy होगा।
- GST system में अधिक participation।
- B2C sector में विकास को बढ़ावा मिलेगा।

57th GST COUNCIL MEETING

Major Recommendation

8 October 2026
(PIB Press Release)



12

E-INVOICING

₹5 करोड़ या अधिक Turnover वाले Taxpayers के कुछ RCM Transactions तक विस्तार



Current Position

E-Invoicing is applicable to Taxpayers with **₹5 करोड़ या अधिक Turnover**.



Proposed Change

₹5 करोड़ या अधिक Turnover वाले Taxpayers के कुछ RCM Transactions तक E-Invoicing का विस्तार किया जाएगा।



Key Points

- 1** **RCM** ₹5 करोड़ या अधिक Turnover वाले Taxpayers के कुछ RCM Transactions को E-Invoicing में शामिल किया जाएगा।
- 2** **Selected RCM Transactions** के लिए E-Invoice Generate करना होगा।
- 3** **E-Invoice** को IRP पर Report करना होगा।
- 4** इससे **RCM Transactions** की transparency और compliance में सुधार होगा।

Expected Benefits

- Better transparency in RCM transactions**
- Improved compliance and tracking**
- Reduction in manual processes and mismatches**

Who Will Be Affected?

- Taxpayers with ₹5 करोड़ या अधिक Turnover**
- Businesses liable to pay GST under Reverse Charge Mechanism (RCM)**
- Sectors with specified RCM transactions (as notified)**

Overall Impact

- Wider coverage of E-Invoicing**
- Stronger tax compliance**
- Improved data visibility for tax authorities**
- More streamlined reporting ecosystem**